लोकसभा चुनाव 2024

रांची, धनबाद एवं पटना से प्रकाशित

शुभम संदेश

एक राज्य - एक अखबार

www.lagatar.in | रांची, शुक्रवार 24 मई 2024 ● ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा संवत 2081 ● पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹ ~~6~~ ● वर्ष : 2, अंक : 45 | आमंत्रण मूल्य : ₹ 3 मात्र

मौसम

शहर	अधिकतम	न्यूनतम
धनबाद	36.9	29.1
जमशेदपुर	35.0	23.0
डालटनगंज	39.6	27.1

तापमान डिग्री सेल्सियस में.

* * *

रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में थमा प्रचार, वोट कल

शुभम किशोर। रांची

लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार (25 मई) को छठे चरण का मतदान होना है. मतदान से पूर्व गुरुवार की शाम प्रचार का शोर थम गया. झारखंड में तीसरे चरण में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह लोकसभा में मतदान होना है. इन चारों सीटों में राज्य के 6 जिले और 24 विधानसभा क्षेत्र आते है. चार सीटों पर 93 प्रत्याशी मैदान में है. रांची से 27, धनबाद से 25, गिरिडीह से 16 और जमशेदपुर से 25 प्रत्याशी मैदान में हैं.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक छठे चरण में झारखंड के 82 लाख 16 हजार 506 मतदाता भागीदारी निभाएंगे. जिसमें 42 लाख 06 हजार 926 पुरुष और 40 लाख 09 हजार 260 महिला मतदाता हैं. सबसे अधिक मतदाता धनबाद में 22 लाख 85 हजार 237 है. वहीं रांची में 24 लाख 97 हजार 331, जमशेदपुर में 18 लाख 69 हजार 278 और गिरिडीह में 18 लाख 64 हजार 660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

झारखंड में तीसरा चरण | 93 प्रत्याशी मैदान में

किस लोकसभा में कितने केंद्र

- रांची- 2377 (949 शहरी, 1428 ग्रामीण)
- धनबाद- 2539 (1316 शहरी, ग्रामीण 1223)
- जमशेदपुर- 1887 (शहरी 688, ग्रामीण 1199)
- गिरिडीह- 2160 (408 शहरी, 1752 ग्रामीण)

कुल लोस सीट - 4

कुल मतदाता 82,16,506

पुरुष मतदाता 42,06,926 | महिला मतदाता 40,09,260

फर्स्ट टाइम वोटर - 2,49,994

100+ वोटर -	766
पोलिंग स्टेशन -	8963
बैलेट यूनिट -	21511
कंट्रोल यूनिट -	10756
वीवी पैट -	11652
पोलिंग पर्सन -	35852

किस लोकसभा में कितने मतदाता

विधानसभा	पुरुष	महिला	कुल
रांची	11,12,524	10,84,738	21,97,331
धनबाद	11,96,501	10,88,656	22,85,237
गिरिडीह	9,60,489	9,04,163	18,64,660
जमशेदपुर	9,37,412	9,31,733	18,69,728

छठे चरण के लिए थमा प्रचार 58 सीटों पर 900 उम्मीदवार

एजेंसी। नयी दिल्ली

लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार गुरुवार शाम समाप्त हो गया. छठे दौर में शनिवा को आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है. इसमें जम्मू-कश्मीर का अनंतनाग-राजौरी भी है, जहां मतदान तीसरे चरण की बजाय छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था.

पूर्व मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरहुआ, महबूबा मुफ्ती व मनोहर लाल समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा. छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें यूपी की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी सात, ओडिशा की छह और झारखंड की चार सीटें शामिल हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर भी लोग वोट डालेंगे. 2019 में इन 58 में से 40 सीटें भाजपा ने जीती थीं. वहीं दूसरे स्थान पर बसपा के खाते में चार सीटें गई थीं. कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था. पिछले चुनाव में इन 58 सीटों पर कुल 64.22% वोट पड़े थे. सबसे ज्यादा 84.59% मतदान बंगाल में हुआ था. वहीं, सबसे कम 8.98% मतदान जम्मू-कश्मीर में दर्ज किया गया था. पड़ोसी बिहार की 8 सीट (वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, शिवहर और महाराजगंज) भी शामिल हैं. बिहार में छठे चरण में 86 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. इसमें 8 पुरुष और आठ महिलाएं हैं. 86 में से 35 निर्दलीय हैं. जबकि 23 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से मैदान में हैं. वैशाली में सबसे अधिक 15 और महाराजगंज में सबसे कम पांच प्रत्याशी मैदान में हैं. बिहार की आठ सीटों पर 1,49,32,165 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. 78,23,793 पुरुष, 71,07,944 महिला और 428 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. पहली बार वोटिंग करने वाले 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 2,12,496 है.

बिहार की 8 सीटों पर 58 प्रत्याशी मैदान में

सर्राफा

सोना (बिक्री)	68,000
चांदी (किलो)	92,000

ब्रीफ खबरें

बंगाल की खाड़ी में आ रहा भीषण तूफान

कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे एक तूफान के भीषण चक्रवात में तब्दील हो 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तट पर पहुंचने की संभावना है. चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के कई इलाकों में भारी बारिश जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसका असर पड़ोसी झारखंड और ओडिशा में भी पड़ने के आसार हैं.

छग में सात नक्सली मुठभेड़ में हुए ढेर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सली और जवानों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई. नक्सल प्रभावित इलाका नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है. वहीं घटना स्थल से अब तक दो नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है. इसकी घटना की पुष्टि नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने की है.

धैर्य की परीक्षा मत लो प्रज्वल, लौट आओ

बेंगलुरु। पूर्व पीएम और जद (सेक्युलर) के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने अपने पोते और यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को देश लौटने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर रेवन्ना पर लगे आरोप सही निकले, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. प्रज्वल रेवन्ना को मेरी चेतावनी शीर्षक वाले दो पन्नों के खुले पत्र में, 91 वर्षीय नेता ने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने पोते की कथित गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी.

अचानक नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार

मुंबई। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण की वोटिंग से पहले भारतीय शेयर बाजार ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए नई ऊंचाई को छू लिया है. शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक- सेंसेक्स और निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया. गुरुवार के कारोबारी सत्र के बाद सेंसेक्स पहली बार 1,196.98 (1.61%) अंकों की बढ़त के साथ 75,418.04 पर बंद हुआ. निफ्टी 354.66 (1.57%) अंकों की उछाल के साथ पहली बार 22,967.65 पर बंद हुआ.

ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने फैलाई सनसनी

अडानी ने खराब कोयला को बढ़िया बता तीन गुना ज्यादा दाम पर बेचा!

शुभम संदेश नेटवर्क। नयी दिल्ली

ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देकर एक खबर प्रकाशित की है. इसने राजनीति और कारपोरेट जगत में खलबली मचा दी है. इसमें दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टीएएनजीईडीसीओ) को कम गुणवत्ता वाला कोयला (3500 कैलोरी प्रति किलो) को 6000 कैलोरी प्रति किलो वाली कोयला बताकर तीन गुणा कीमत पर बेचा. समूह ने जिस कोयला को उच्च क्वालिटी का बताया और स्वच्छ ईंधन के नाम पर ज्यादा दाम पर बेचा, असल में वही खराब कोयला था. चुनावी माहौल में इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है.

- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा- घटिया कोयला सप्लाई मामले की इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही कराएंगे जेपीसी से जांच

पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इसे घोटाला करार देते कहा है कि इस घोटाले के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र ने कम गुणवत्ता वाले कोयले को तीन गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं. इसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है. प्रदूषण को भी नुकसान पहुंचा है. कांग्रेस ने दावा किया है कि चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो इस तरह के मामलों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जाएगी. वह इन आरोपों की जांच करेगी. राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है. सालों से चल रहे इस घोटाले के ज़रिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो-ग्रेड कोयले को तीन गुने दाम पर बेच कर हज़ारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई. क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को शांत रखने के लिए कितने टेंपो लगे? चार जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार इस महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई-पाई का हिसाब करेगी.

क्या हैं आरोप, कैसे मामले ने पकड़ा तूल

क्या कहती है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट

ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रुप सरकारी बिजली कंपनी के साथ लेनदेन के दौरान घटिया किस्म के कोयले को कहीं ज्यादा महंगे स्वच्छ ईंधन के तौर पर बेचने में शामिल था. अखबार ने दावा किया उसकी रिपोर्ट साक्ष्यों पर आधारित है, जो लंबे समय से चल रहे कोयला घोटाले के आरोपों पर नई रोशनी डालती है. रिपोर्ट कहती है कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखा है. फाइनेंशियल टाइम्स ने इन दस्तावेजों की समीक्षा की है. ब्रितानी अखबार ने कहा है कि भारतीय समूह से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप संभावित पर्यावरणीय आयाम जोड़ते हैं. दस्तावेजों से पता चलता है कि मुमकिन है कि अडानी ग्रुप ने एयर क्वालिटी (हवा को खराब करना) की कीमत पर धोखाधड़ी से बंपर मुनाफा कमाया हो. ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली के लिए निम्न-श्रेणी के कोयले का इस्तेमाल करने का मतलब है कि ईंधन का अधिक उपयोग होना. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इनवॉयस से पता चलता है कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशियाई कोयले की एक खेप खरीदी थी. इसमें प्रति किलोग्राम 3,500 कैलोरी होने की सूचना दी गई थी. इस खेप को फिर तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (टीएएनजीईडीसीओ) को 6,000 कैलोरी वाले कोयले के रूप में बेचा गया. इसे सबसे मूल्यवान ग्रेड में से एक माना जाता है. रिपोर्ट में संदेह जताया गया है कि ऐसा लगता है कि परिवहन लागत को ध्यान में रखते हुए अडानी ने शुरुआती निवेश से दोगुना से भी अधिक पैसा कमाया है. रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग आउटडोर एयर पलूशन के कारण मरते हैं. यह जानकारी द लैंसेट में प्रकाशित 2022 के एक अध्ययन पर आधारित है. इसके अलावा अन्य अध्ययनों से पता चला है कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के बड़े दायरे में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि जनवरी 2014 में अडाणी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से 28 डॉलर प्रति टन की कथित कीमत पर लो-ग्रेड कोयला खरीदा था. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस शिपमेंट को तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में 91.91 डॉलर प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया गया था.

पहले भी लगे थे अडानी ग्रुप पर कोल इंपोर्ट बिल में हेरी-फेरी के आरोप

फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कम रेट में कोयला इंपोर्ट किया. बिल में हेराफेरी करके ज्यादा दाम दिखाए. ग्रुप ने कोयले से जनरेट होने वाली बिजली को ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेची. अखबार ने 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में ग्रुप के इंडोनेशिया से भारत इंपोर्ट हुए 30 कोयले शिपमेंट की जांच की. इन सभी के इंपोर्ट रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की तुलना में कीमतें ज्यादा मिलीं. रकम 582 करोड़ बढ़ाई गई. तमिलनाडु बिजली बोर्ड का गठन एक जुलाई, 1957 को बिजली अधिनियम 1948 की धारा 54 के तहत राज्य में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया था. फिर नेटवर्क को राज्य के सभी गांवों तक फैलाया गया.

अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट का उड़ाया मजाक

वहीं, कथित कोयला घोटाले का दावा करने वाली फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर अडाणी समूह के सीएफओ (चीफ फाइनेंस ऑफिसर) जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने एक्स पर मजाक उड़ाते हुए लिखा- 1757 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन को भारत का उपनिवेश क्यों बनाना पड़ा. इस पर एफटी, बीबीसी की प्रमुख जांच रिपोर्ट. जांच रिपोर्ट का सारांश- अडानी समूह के गठन को रोकने के लिए अब आप सब कुछ जानिए. अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा और निराधार बताया है.

संजीव लाल की डायरी में ईडी को मिले...

मंत्री बादल, हफीजुल समेत 150 नेता, अफसर, इंजीनियरों के नाम

सौरभ सिंह। रांची

ग्रामीण विकास विभाग में हुए कथित टेंडर घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मिली डायरी में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, खेल मंत्री हफीजुल हसन के भी नाम शामिल हैं. इसके अलावा 150 से अधिक राजनेता, अफसर, इंजीनियर व ठेकेदारों के नाम भी डायरी में दर्ज हैं. ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घर से यह डायरी बरामद की है. जिसके आधार पर संबंधित लोगों को समन भेजा जा रहा है. इस बीच भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि ईडी जल्द ही सरकार के इन दोनों मंत्रियों को समन करने जा रही है. गौरतलब है कि ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के करीबी जहांगीर आलम के घर में छापेमारी कर 35 करोड़ रुपए नकद बरामद किये थे. जिसके बाद ईडी ने संजीव लाल व जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने दो दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार किया था. तीनों अभी ईडी की हिरासत में हैं.

उल्लेखनीय है कि ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाला करीब 3000 करोड़ रुपए का है. इन पैसे में से अफसरों, नेताओं व इंजीनियरों को हिस्सा मिलता था. मंत्री और अफसरों के नाम कोड वर्ड में लिखे हैं. इसी मामले में बुधवार को ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को समन भेजा है. ईडी ने उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है.

ईडी जल्द कर सकती है पूछताछ

- ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घर से यह डायरी बरामद की है. जिसके आधार पर संबंधित लोगों को समन भेजा जा रहा है.

कमीशन की राशि फिक्स

ईडी ने अब तक की जांच में पाया है कि ग्रामीण विकास विभाग के ठेकों में निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर मंत्री तक को कमीशन की राशि फिक्स थी. ईडी ने कोर्ट को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उसमें ठेकों के लिए एलओए (लेटर ऑफ एक्सेप्टेशन) जारी होने पर ही कमीशन मिल जाने का उल्लेख भी किया गया है. जनवरी महीने में 25 छोटे-छोटे ठेकों के बाद ही मंत्री आलमगीर आलम के लिए 1.23 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर मिलने का जिक्र डायरी के एक पन्ने में भी किया गया है.

आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास

प्रसंगवश

बैजनाथ मिश्र

वरिष्ठ पत्रकार और झारखंड के पूर्व सूचना आयुक्त

तुलसी ने रामचरित मानस में लिखा है-करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा. यहां करम का मतलब भाग्य नहीं कर्म है. किसी को यह कर्मफल विलंब से मिलता है, लेकिन खुद को चालबाजी में तुर्रम खां समझने वालों को शीघ्र मिल जाता है. यकीन न हो तो स्वयं को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझने वाले केजरीवाल की हालत देख लीजिए. सरकती जाये रुख से नकाब अहिस्ता-अहिस्ता. उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है. केवल दस साल में क्या से क्या हो गया. ये आये थे गलीच राजनीति बदलने, लेकिन धतकर्मों के रिकॉर्डधारी बन गये हैं. ताजा मामला एक महिला सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई का है. वह भी मुख्यमंत्री आवास में. इस मामले में केजरीवाल के राजदार पीए विभव कुमार गिरफ्तार हो गये हैं. इस पर एक महिला मंत्री का कहना है कि यह सब केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भाजपा की साजिश है. यदि यह सही है तो लखनऊ की प्रेस कांफ्रेंस में इस बारे में पूछे गये सवाल पर केजरीवाल माइक दायें-बायें क्यों खिसका रहे थे ? इस बाबत तो पहला सवाल यही है कि क्या मालीवाल आप की सांसद नहीं हैं ? यह भी कि क्या वह केजरीवाल के साथ तब से नहीं हैं जब वह एनजीओ चलाते थे ? तब इस महिला मंत्री का अता-पता नहीं था.

आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि मालीवाल मुलाकात का समय लिये बिना सीएम से मिलने पहुंच गईं और रक्षकों को डरा-धमका कर अंदर चली गईं. वह जब ड्राइंग रूम में इंतजार करने के बाद आवास के अंदर जाने लगीं, तब उन्हें विभव कुमार ने रोका, तो उनसे झगड़ बैठीं और अपनी प्रताड़ना की झूठी मौखिक रिपोर्ट पुलिस को भेज दी. बहरहाल अब तो उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करा दी है और अदालत में अपना स्वीकारोक्ति बयान भी दे दिया है. उसके बाद ही विभव कुमार को सीएम आवास से दबोचा गया है. लेकिन यदि मंत्री महोदया का आरोप सही है तो आप के ही सांसद संजय सिंह ने प्रेस के सामने यह क्यों कहा था कि विभव ने मालीवाल के साथ निंदनीय कृत्य किया है, केजरीवाल ने इसका संज्ञान भी लिया है और वह विभव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? आखिर झूठ कौन बोल रहा है ? शायद दोनों ही झूठे हैं. आखिर दोनों ही अराजक शिरोमणि केजरीवाल के चट्टे-बट्टे हैं.

पहले लगा कि संजय सिंह को मध्यस्थता के लिए लगाया गया है और घर की बात घर में ही सुलझ जाएगी. लेकिन जब अगले ही दिन केजरीवाल संजय सिंह और विभव कुमार को लेकर लखनऊ उड़ गये तब यह साफ हो गया कि केजरीवाल इस घटना से तनिक भी आहत नहीं हैं और इसीलिए यह कयास लगाया जाने लगा कि केजरीवाल के कहने पर ही मालीवाल की पिटाई हुई है. फिर क्या था मालीवाल की पीड़ा दोगुनी हो गयी और यह मामला पुलिस के जरिये अदालत में पहुंच गया, एम्स में मेडिकल जांच भी हो गयी जिसमें चोट की पुष्टि हो गयी. क्या मालीवाल बिना समय लिए केजरीवाल से नहीं मिलती रही हैं ? यदि उनके लिए भी नियम वही था जो जन सामान्य या अन्य नेताओं के लिए है, तो फिर उनकी पिछली मुलाकातों और समय निर्धारण का विवरण सीएम आवास जारी क्यों नहीं कर रहा है ?

मालीवाल केजरीवाल की इतनी करीबी थीं कि उन्हें वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाये रखा गया और वहां से रुखसती के बाद पहली फुर्सत में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया. इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह पहले भी बिना समय लिये केजरीवाल से मिलती रही होंगी, लेकिन इस बार मिलने की वजह कुछ ऐसी होगी या कोई हुकुमउदूली हुई होगी जो इरादतन, शरारतन उनकी पिटाई हो गई. -शेष पेज 12 पर

कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, कितने लोग होंगे प्रभावित

पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म

एजेंसी। कोलकाता

चुनाव के बीच बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं. हाईकोर्ट ने फैसले में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक ओबीसी के तहत मुस्लिमों को 77 श्रेणियों में दिए आरक्षण व 2012 के कानून के तहत इनके लिए बनाई 37 श्रेणियों को निरस्त कर दिया.

कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले के दिन से ही रद्द प्रमाणपत्रों का किसी भी रोजगार प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जा सकेगा. इससे करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएंगे. जस्टिस तपोन्नत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने हालांकि यह भी कहा कि इन प्रमाणपत्रों से जिन उम्मीदवारों को पहले मौका मिल चुका है, उन पर फैसले का असर नहीं होगा. पीठ ने फैसले में तृणमूल सरकार का जिक्र नहीं किया है। संयोग से तृणमूल 2011 से राज्य की सत्ता में है. इसलिए कोर्ट का आदेश सिर्फ तृणमूल सरकार में जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों पर प्रभावी होगा.

> इन जातियों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। हमारा मानना है, मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़े के रूप में चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है।
>
> कलकत्ता हाईकोर्ट